Daily Current Affairs 16/07/2021

1. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक 4607.30 करोड़ रुपये के वित्तीय व्यय के साथ जारी रखने को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) के बारे में:

- केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन को **आयुष मंत्रालय, भारत सरकार** द्वारा लागू किया जा रहा है।
- **आयुष विभाग,** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 12वीं योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से लागू करने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया है।
- आयुष मिशन 15 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था।

उद्देश्य: राष्ट्रीय आयुष मिशन का मूल उद्देश्य लागत प्रभावी आयुष सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन के घटक:

अनिवार्य घटक

- आयुष सेवाएं
- आयुष शैक्षणिक संस्थान
- ASU और H औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण (आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा रिग्पा, यूनानी और होम्योपैथी भी)

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- औषधीय पौधे

नम्य घटक

- योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्र
- टेली-मेडिसिन
- सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित आयुष में नवाचार
- स्वैच्छिक प्रमाणन योजना: परियोजना आधारित
- मार्केट प्रमोशन, मार्केट इंटेलिजेंस और बाय बैक इंटरवेंशन

केंद्रीय कल्याण योजनाओं के बारे में:

- केंद्रीय कल्याण योजनाओं को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: **(i) केंद्र प्रायोजित योजनाएं, (ii) केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं।**

(i) केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS):

- केंद्र प्रायोजित योजनाएं वे योजनाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एक परिभाषित शेयरधारिता के साथ प्रायोजित की जाती हैं।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं को पुनः **दो वर्गों- कोर ऑफ कोर स्कीम्स** और **कोर स्कीम्स** में विभाजित किया जा सकता है।

कोर स्कीम्स: हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्कूलों में मध्याह्न भोजन और राष्ट्रीय आजीविका मिशन कुछ प्रमुख योजनाएं हैं।

कोर ऑफ कोर स्कीम्स: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, अन्य कमजोर समूहों और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना।

(ii) केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं:

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और योजना के लिए आवश्यक बजट या वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- **उदाहरण के लिए,** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

स्रोत: PIB

2. NTPC की नई सौर परियोजनाएं

चर्चा में क्यों?

- **NTPC की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड** ने इस क्षेत्र में **देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना (ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट)** स्थापित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- MoU पर हस्ताक्षर को लेह में सोलर ट्री और सोलर कार पोर्ट के रूप में **NTPC के पहले सोलर इंस्टॉलेशन** के उद्घाटन के साथ भी चिह्नित किया गया था।
- NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड **गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में 4,750 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पार्क** स्थापित करेगी। यह **भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा।**

प्रमुख बिंदु

हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना:

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- समझौता ज्ञापन NTPC को अक्षय स्रोतों और हरित हाइड्रोजन के आधार पर लद्दाख को कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था विकसित करने में मदद करेगा।
- NTPC ने इस क्षेत्र में शुरुआत करने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसें चलाने की योजना बनाई है। कंपनी लेह में एक सौर संयंत्र और एक हरित हाइड्रोजन उत्पादन इकाई भी स्थापित करेगी।
- इससे लेह हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन जाएगा।

भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क:

- NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड **अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क योजना** के तहत **गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में 4,750 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पार्क** स्थापित करेगी। यह **भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा**।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को यह मंजूरी सोलर पार्क योजना के मोड 8 (अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क) के तहत दी है।
- NTPC आरईएल की इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने की योजना है।

NTPC के बारे में:

- NTPC लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न PSU है।

NTPC लक्ष्य:

- NTPC ने हाल ही में 2032 तक 60 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को संशोधित किया है, जो पिछले लक्ष्य को लगभग दोगुना कर देता है।

NTPC की परियोजना:

- हाल ही में, NTPC ने विशाखापत्तनम में भारत की 10 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू की है।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- तेलंगाना स्थित रामागुंडम ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है।

अन्य सौर ऊर्जा पहल:

राष्ट्रीय सौर मिशन:

- यह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक पहल है।
- यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की कई नीतियों में से एक है।
- कार्यक्रम का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 11 जनवरी 2010 को 2022 तक 20 गीगावाट के लक्ष्य के साथ किया था।
- इसे बाद में भारत के 2015 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बढ़ाकर 100 गीगावाट कर दिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस (ISA) के बारे में:

- ISA को भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, या COP21 के दौरान पेरिस में लॉन्च किया गया था।
- **मुख्यालय:** गुरुग्राम, हरियाणा, भारत
- **स्थापना:** 30 नवंबर 2015

स्रोत: PIB

3. न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं का विकास

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने **न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास** के लिए **केन्द्र प्रायोजित योजना** को कुल 9,000 करोड़ रुपये की लागत में 01 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक और पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है।
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिये **ग्राम न्यायालय योजना** तथा **न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिये राष्ट्रीय मिशन** के ज़रिये मिशन मोड में 50 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय न्याय वितरण और कानूनी सुधार मिशन (NMJDLR) के बारे में:

- इसे 2011 में दोहरे लक्ष्यों के साथ शुरू किया गया था। पहला देरी और बकाया को कम करके पहुंच बढ़ाना है और दूसरा संरचनात्मक परिवर्तन और प्रदर्शन मानकों को स्थापित करके जवाबदेही बढ़ाना है।
- न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना 1993-94 से चल रही है।
- इस प्रस्ताव से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए 3800 कोर्ट हॉल और 4000 आवासीय इकाइयों (नई और वर्तमान में चल रही, दोनों किस्म की परियोजनाओं), वकीलों के लिए 1450 हॉल, 1450 शौचालय परिसरों और 3800 डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण में मदद मिलेगी।

ग्राम न्यायालय:

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदानों को प्रमाणित करके ग्राम न्यायालयों को समर्थन देने के निर्णय को भी मंजूरी दी।
- **ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008,** जोकि 2 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ था, को देश के ग्रामीण इलाकों में न्याय प्रणाली तक त्वरित और आसान पहुंच बनाने के उद्देश्य से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए लाया गया था।

योजना की निगरानी

- न्याय विभाग द्वारा *एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली* स्थापित की गई है जो प्रगति, निर्माणाधीन कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के पूरा होने से संबंधित डेटा संग्रह के साथ-साथ बेहतर परिसंपत्ति प्रबंधन को संभव बनाती है।
- न्याय विभाग ने ISRO की तकनीकी सहायता से एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित की है।
- उन्नत वेब पोर्टल **"न्याय विकास-2.0"** और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग CSS न्यायिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है।
- **ग्राम न्यायालय पोर्टल** इस योजना को लागू करने वाले राज्यों द्वारा ग्राम न्यायालयों के कामकाज की ऑनलाइन निगरानी में मदद करता है।

स्रोत: PIB

4. सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA 17% से बढ़ाकर 28% किया

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

चर्चा में क्यों?

- कैबिनेट ने 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी।
- इसके साथ ही DA की नई दर 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- देश में महामारी की चपेट में आने के कारण 2020 में DA और DR फ्रीज़ कर दिए गए थे।
- 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच की अवधि के लिए DA की दर 17 प्रतिशत रहेगी।

महंगाई भत्ते (DA) के बारे में:

- महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई और भत्ते की गणना है।
- DA साल में दो बार संशोधित किया जाता है - एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

5. भारत वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा

चर्चा में क्यों?

- भारत 2026 में BWF (बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन) वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।

प्रमुख बिंदु

- यह केवल दूसरी बार होगा जब भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, हैदराबाद ने 2009 में प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी की थी।
- भारत को 2023 में सुदीरमन कप का आयोजन करना था, लेकिन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने चीन को वर्ल्ड मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप की मेजबानी के अधिकार देने का फैसला किया।

बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) के बारे में तथ्य:

- BWF अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त बैडमिंटन के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है।
- **मुख्यालय:** कुआलालंपुर, मलेशिया
- **स्थापना:** 5 जुलाई 1934

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

6. शेर बहादुर देउबा ने 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली

- नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
- **नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी** ने शेर बहादुर देउबा को पद की शपथ दिलाई।
- **नोट:** शेर बहादुर देउबा को संविधान के अनुच्छेद 76(5) के तहत प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जो उनके लिए शपथ लेने के 30 दिनों के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना अनिवार्य बनाता है।
- उन्होंने इससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में 4 कार्यकाल (1995-1997, 2001–2002, 2004–2005 और 2017–2018) में कार्य किया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

gradeup

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams

Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now